

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 869
07 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए नियत
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

869. श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री रवि किशन:

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) मध्य प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;
- (घ) उक्त योजना के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरियों को बदलने की सुविधा प्रदान करने अथवा बैटरी स्वैपिंग प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:-

- i. सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहनों के उत्सर्जन के मुद्दों के निवारण के लिए 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-1। को अधिसूचित किया है। इस चरण का उद्देश्य 7090 ई-

बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों (स्ट्रॉंग हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करके मांग सृजित करना है।

- ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने दिनांक 15 सितंबर 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम अनुमोदित की। ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोटर वाहन विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में देश में 50 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

(ख): फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II को मध्य प्रदेश राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। मांग प्रोत्साहन की मात्रा बैटरी क्षमता से जुड़ी है अर्थात् ई-तिपहिया और ई-चौपहिया के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा जो सभी पात्र वाहनों की लागत के 20% प्रतिशत की सीमा के अध्यक्षीन है। साथ ही, 11 जून, 2021 से ई-दुपहिया के लिए वाहनों की लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करके मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया गया है।

(ग): फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी गई है।

(घ): फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II को देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ): नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति को कार्यान्वित करने के लिए हितधारकों के परामर्श हेतु अपनी वेबसाइट पर एक मसौदा नीति अपलोड की है। बैटरी स्वैपिंग नीति के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

बैटरी स्वैपिंग का उपयोग आम तौर पर दुपहिया और तिपहिया जैसे छोटे वाहनों के लिए किया जाता है, जिसमें छोटी बैटरी होती है, जिन्हें चौपहिया वाहनों और ई-बसों की तुलना में स्वैप करना आसान होता है, हालांकि चौपहिया वाहनों और ई-बसों के लिए भी समाधान उभर रहे हैं। चार्जिंग के सापेक्ष बैटरी स्वैपिंग के तीन प्रमुख फायदे हैं: यह समय, स्थान और लागत कुशल है, बशर्ते प्रत्येक स्वैपेबल बैटरी सक्रिय रूप से उपयोग की जाए।
